GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
STRARRED QUESTION NO. *79
ANSWERED ON 09.02.2021

TRADING IN CRYPTOCURRENCY

79#. SHRI SUSHIL KUMAR MODI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a ban was imposed on Bitcoin trading in 2018 which was later on lifted by the Hon'ble Supreme Court;

(b) whether other cryptocurrencies are still under ban;

(c) whether it is also a fact that despite the ban, illegal trading of cryptocurrency is still being done on a large scale; and

(d) if so, by when Government proposes to issue strict guidelines in this regard keeping in view the risk involved therein?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANURAG SINGH THAKUR):

(a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 79# RAISED BY SHRI SUSHIL KUMAR MODI, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 09.02.2021 REGARDING 'TRADING IN CRYPTOCURRENCY'

(a) to (c) In view of the risks associated with Virtual Currencies (VCs), including Bitcoins, Reserve Bank of India (RBI), vide circular dated April 6, 2018, had advised all the entities regulated by it not to deal in VCs or provide services for facilitating any person or entity in dealing with or settling VCs.

However, the Hon'ble Supreme Court, vide judgement dated March 4, 2020 in WP (C) No. 528 of 2018 and WP (C) No. 373 of 2018, had set aside the above circular dated April 6, 2018.

(d) It was announced in the Budget Speech for 2018-19 that "The Government does not consider crypto-currencies legal tender or coin and will take all measures to eliminate use of these crypto-assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system. The Government will explore use of block chain technology proactively for ushering in digital economy." A High-Level Inter-Ministerial Committee (IMC) constituted under the Chairmanship of Secretary (Economic Affairs) to study the issues related to VCs and propose specific actions to be taken in this matter recommended in its report that all private cryptocurrencies, except any cryptocurrency issued by the State, be prohibited in India. The Government would take a decision on the recommendations of the IMC and the legislative proposal, if any, would be introduced in the Parliament following the due process.

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 79#

(जिसका उत्तर मंगलवार 09 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है)

क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार

79#. श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिटकॉइन के कारोबार पर वर्ष 2018 में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था;

(ख) क्या अन्य क्रिप्टोकरेंसियों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी का अवैध व्यापार चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसके जोखिम को देखते हुए कब तक कड़े दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार" के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 79 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसियों (वीसी) से संबंधित जोखिमों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के जरिए उसके द्वारा विनियमित निकायों को वर्चुअल करेंसियों का व्यापार और वीसी में व्यापार अथवा निपटान में किसी व्यक्ति अथवा निकाय को सुकर बनाने के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करने की सलाह दी थी।

तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04 मार्च, 2020 की रिट याचिका (सी) सं.2018 की 528 तथा रिट याचिका (सी) सं. 2018 की 373 में निर्णय के जरिए दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के उक्त परिपत्र को हटा दिया गया था।

(घ) 2018-19 के लिए बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि "सरकार क्रिप्टोकरेंसियों अथवा सिक्कों को वैध मुद्रा नहीं मानती है और भुगतान तंत्र के भाग के रूप में अवैध कार्यकलापों को वित्तपोषित करने में इन क्रिप्टो-आस्तियों के उपयोग को समाप्त करने के संबंध में सभी उपाय करेगी। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में संचालन के लिए ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग करने की तलाश करेगी।" वीसी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस मामले में की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों को प्रस्तावित करने के लिए गठित सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि राज्य द्वारा जारी किसी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसियां भारत में निषिद्ध हों। सरकार आईएमसी की अनुशंसाओं पर निर्णय करेगी और विधायी प्रस्ताव, यदि कोई हो, समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संसद में पुर:स्थापित करेगी।

*****

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Yes, Sir. Q. No. 79.

श्री सभापति: शक्तिसिंह जी, मैंने दिनेश त्रिवेदी जी को बुलाया है। क्या इसमें आपका नाम है? मैं आपको बुलाऊँगा, बैठिए। आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं आपको बुलाऊँगा। दिनेश त्रिवेदी जी कहाँ हैं? ...(**व्यवधान**)... उन्होंने स्लिप भेजी है। Okay. Shri K.C. Ramamurthy.

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, there is no doubt that the problem of bitcoins and other cryptocurrencies has escalated. The circular issued by the RBI has a limited impact. I would like to know from hon. Finance Minister whether there is any proposal to bring in a Bill to curb cryptocurrencies in the country.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the regulatory bodies like the RBI, SEBI, etc., don't have any legal framework to directly regulate cryptocurrencies as they are neither currencies nor assets nor securities nor commodities issued by identifiable users. The existing laws are inadequate to deal with the subject. The Government formed an Inter-Ministerial Committee which has given its report. Then there was a meeting of the Empowered Technology Group. Then the Committee of Secretaries chaired by the Cabinet Secretary has also given its report. The Bill is being finalized and it will soon be sent to the Cabinet. We will soon be bringing a Bill.

श्री शक्तिसिंह गोहिल: माननीय सभापति महोदय, यह इश्यू खासकर गुजरात के सूरत में बहुत seriously impact करता है। एक ओर सरकार ने RBI के circular के ज़रिए इसको रोकने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके circular को खारिज कर दिया, which means bitcoin चल सकता है। In the Minister's reply, (d) में ये कह रहे हैं कि हमने इसको announce किया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसका कानून लेकर आ रहे हैं, Ministerial Group बना है। सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिए यह जानना चाहता हूँ कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में यह मानते हैं कि यह गलत है, तो इसके खिलाफ review petition दाखिल की गयी है या नहीं? And the second is, in Surat.....

MR. CHAIRMAN: Only one supplementary please.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, if you see globally, there are different definitions of crypto currencies or virtual currencies adopted by international bodies. The RBI also took initiative and banned the use of private crypto currencies. As Member has rightly said, there was an order of the Supreme Court. That is why, the Government of India took an initiative. There was an inter-Ministerial committee. That Committee gave its report. As I said earlier, Committee of Secretaries also met

under the chairmanship of the Cabinet Secretary. They have given their report. Now, the Government has prepared a Bill and it will be brought forward in the Parliament. Soon, we can have a detailed discussion on that.

MR. CHAIRMAN: Q.No.80; Shri G.V.L. Narasimha Rao; not present. The Minister may lay it. Any supplementaries!?

*